ारा मिन्न किसी अन्य प्रयोजी हेत वारता

हा प्रेषका । इंक हैं के प्रेष्ट्र के किया है जिस्से के प्रेष्ट्र के स्वापन हैं के अपने किया है कि अपने एन०एस०नपलच्याल, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें.

जिलाधिकारी, देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः जून, 2008

विषय:- मै0 जय भगवान एजुकेशनल सोसायटी को तकनीकी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम शंकरपुर हकुमतपुर में 0.8680 है0 अतिरिक्त भूमि क्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1864 / 12ए-226 (2005-08) डी० एल० आर० सी0 दिनांक 26 मई, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जय भगवान एजुकेशनल सोसायटी को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत होटल मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट (तकनीकी शैक्षणिक संस्थान) की स्थापना हेत् जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम शंकरपुर हकुमतपुर के खसरा नम्बर 2234 रकवा 0.8680 है0 अतिरिक्त भूमि कय करने की अनुमित निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी रिथति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अई होगा।
- 2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके वाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

**राष्ट्रवाद्र२५०**२२०वस्य / 18(३) / 2001

例如认

enálií.

ं एक हाली के **के ल**ें

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा—167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की रिथिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमित प्राप्त की जायेगी।

5— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

- 6— शासन द्वारा दी गयी भूमि कय की अनुमित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी। उक्त अविध के भीतर प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- 7— संस्था द्वारा भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष के भीतर भूमि का उपयोग तकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु कर लिया जायेगा।
- 8— संस्था द्वारा भूमि के विकय विलेख की पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के भीतर तकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु नियमानुसार एआईसीटीई को आवेदन कर दिया जायेगा। जिसकी एक प्रति तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- 9— क्य की जाने वाली भूमि पर उतने ही तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे जितने एआईसीटीई के मानकनुसार अनुमन्य हैं।
- 10— किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमित नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।
- 11— भूमि का विक्रय अारेहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी ...(3)

क्रमाह किलानी प्राप्त क

दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- 12— योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों / संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें / अनापित्तियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 13— उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय, (एन०एस०नपलच्याल) प्रमुख सचिव।

## संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्रम एव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
- 4- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 5- आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।

**W**ALL CONTRACT CONTRACT

- ,6—. श्री रंजन सिंघल, सचिव, मै० जय भगवान एजुकेशनल सोसायटी, 17 मन्दिरमार्ग, बसन्तविहार इन्कलेव देहरादून।
- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल। विव

आज्ञा से, जिले (सन्तोष बडोनी) अनुसचिव।